2022 तक 28 हजार मेगावाट हो जाएगी ट्रांसमिशन क्षमता : श्रीकांत

लखनऊ। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के युद्धस्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। 2022 तक प्रदेश में बिजली की ट्रांसमिशन क्षमता 28 हजार मेगावाट तक करने का लक्ष्य है। इस पर 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बीते चार वर्षों में ट्रांसशिन क्षमता को बढ़ाकर 25000 मेगावाट तक पहुंचाया जा चुका है। अगले साल तक यह 28000 मेगावाट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक 12 हजार 182 करोड़ रुपये से 121 ट्रांसमिशन उपकेंद्रों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश में स्थापित की जा रही तापीय परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति करना चाहती है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब ट्रांसमिशन सभी क्षेत्रों को बिजली ले जाने में सक्षम हो। सरकार बनने के बाद इस पर गंभीरता से काम किया गया है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए 765 केवी के एक, 400 केवी के 12 तथा 220 केवी के 34 उपकेंद्रों का निर्माण कराया गया है। ब्यूरो